PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Sunday, 19th December 2010, Page: 10
Width: 25.06 cms Height: 14.82 cms, Ref: pmin.2010-12-19.35.69

विलय व अधिग्रहण से नई बुलंदियों पर पहुंचा दवा उद्योग

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)। विदेशी कंपनियों के साथ गठबंधन से मजबूत दिख रहा भारतीय दवा उद्योग पूरे साल विलय व अधिग्रहण के कारण सुर्खियों में छाया रहा। इसके साथ देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती पैठ से सस्ती दवाओं की उपलब्धता के प्रति चिंता भी बढ़ने लगी।

भारतीय औषधि कंपनी सनफर्मा ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इजराइल की दवा कंपनी तारो के अधिग्रहण मामले में विजय हासिल की। पीरामल ने अपने दवा कारोबार को अमेरिकी कंपनी एबोट को बेचकर दवा उद्योग को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। बायोकॉन की फाइजर के साथ हुई मार्केटिंग डील से भी भारतीय दवा उद्योग को मजबूती मिली। वास्थ्य देखभाल और हॉस्पिटल क्षेत्र में पार्कवे को हथियाने में मात खाने के बाद फोर्टिस ने हांगकांग की क्वालिटी हेल्थकेयर एशिया का अधिग्रहण कर सीमापार स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने पांव पसार लिए। ससे वैश्विक क्षेत्र में भारतीय औषधि कंपनियों की आने वाले साल में बढ़ती भूमिका का एहसास हुआ।

लेकिन इस बात को लेकर भारतीय दवा उद्योग में चिंता भी बढ़ी है कि अनुसंधान और विकास के बड़े नेटवर्क और धनबल वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय औषधि कंपनियों की खरीदारी शुरू कर दी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से भारतीय दवा कंपनियों के बढ़ते अधिग्रहण के कारण औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को एक परिचर्चा पत्र में इस सुझाव के साथ आगे आना पड़ा कि औषधि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विदेशी कंपनियों के एक के बाद एक भारतीय दवा कंपनियों के अधिग्रहण से देश में सस्ती दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी। इसको देखते हुए सरकार ने बाद में अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्था की संभावनाओं को टटोलना शुरू कर दिया। इसके तहत दवा के पेटेंटधारक के अलावा तीसरा पक्ष भी पेटेंट दवा या फार्मूले का उत्पादन और विपणन कर सकता है। सरकार ने स्थानीय स्तर पर भी नई खोज और उत्पादों के लिए 2000 करोड़ रुपए का पूंजी उद्यम कोष बनाने की योजना तैयार की। इस कोष के जरिए दवा उद्योग में नए फार्मूले तैयार करने के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। भारतीय दवा कंपनियों को निर्यातित माल के जब्त कर लिए जाने से यूरोपीय संघ और दुनिया के दूसरे हिस्सों में निर्यात कारोबार को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिर में इसी हफ्ते यूरोपीय संघ के साथ इस मुद्दे को सुलझा लिया गया।

वाणिज्य व उद्योग मंडल फिक्की की निदेशक बिशाखा भट्टाचार्य ने कहा कि दवा और स्वास्थ्य देखभाल दोनों क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2020 तक इस उद्योग का कारोबार 280 अरब डालर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। मैकेंजी एंड कंपनी ने कहा कि अगले कुछ सालों में सालाना 14 फीसद की वृद्धि दर के साथ 2015 तक दवा उद्योग का कारोबार 40 अरब डालर तक पहुंच जाएगा। घरेलू बाजार जो कि 14 फीसद सालाना की वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है, 2015 तक इसके 20 से 24 अरब डालर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। वर्तमान में दवा उद्योग का कुल कारोबार 20 अरब डालर तक है जिसमें नौ अरब डालर का निर्यात कारोबार शामिल है।

साल के दौरान घरेलू दवा कंपनियों की विश्व बाजार में अपने पैर पसारने के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने की मंशा भी जाहिर हुई। सनफर्मा ने तीन साल की कड़ी कानूनी लड़ाई के बाद इजराइल की तारो का अंतत नियंत्रण हासिल कर ही लिया। फोर्टिस के मामले में भी कुछ ऐसी ही प्रतिबद्धता नजर आई। कंपनी ने सिंगापुर की अस्पताल श्रृंखला चलाने वाली कंपनी पार्कवे के नियंत्रण के लिए मलेशिया के सरकारी कोष के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा की। इसके बाद फोर्टिस ने हांगकांग की क्वालिटी हेल्थकेअर एशिया लिमिटेड का 882 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की तरफ अपना रुख किया।

इधर घरेलू मोर्चे पर बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों ने अपना रुख किया और भारतीय दवा कंपनियों के सकल या आंशिक कारोबार का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। इससे वैश्विक बाजार में दवा उद्योग के बढ़ते महत्त्व का पता

साल के दौरान बायकॉन का
वा कंपनी फाइजर के साथ 35
र दवा की मार्केटिंग का सौदा
ं में रहा। दवा उद्योग में साल
बड़ा सौदा अमेरिकी बहुराष्ट्रीय
टि की ओर से भारतीय औषधि
ारामल हेल्थकेअर के दवा
ा अधिग्रहण रहा। यह सौदा
डालर का रहा। इस अधिग्रहण
ॉट भारत में प्रमुख दवा निर्माता
अपनी जगह बनाएगी। साल के
अन्य दवा कंपनी सिपला ने भी
म अधिग्रहण करने वाली
के सूची में शामिल करने में
हासिल कर ली। सिपला ने
ी वर्षगांठ के मौके पर घरेलू
टैब स्पेशिलियटी का 133.35
में अधिग्रहण किया।